International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628, Print ISSN: 2664-861X
Received: 01-08-2021, Accepted: 16-08-2021, Published: 06-09-2021
Volume 3, Issue 2, 2021, Page No. 36-38

औपनिवेशिक भारत में जाति व्यवस्था की चुनौतियां

Chitra Raj
PG, Student, (History), IGNOU, Delhi, India

सारांश

भारत में जाति व्यवस्था तो सदियों से विराजमान थी लेकिन औपनिवेशिक काल में एक पुस्तक "The truth about us: The politics of information from manu to Modi" मे दर्शाया गया है कि आधुनिक भारत में धरम ओर जाति की सामाजिक श्रेणियां कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित की गई थी। अंग्रेजो ने भारत के स्वदेशी धर्मो की स्वीकृत सूची बनाई, जिसने हिन्दू, सिख और जैन धरम को शामिल किया गया और उनके ग्रंथो में किए गए दावों के आधार पर धर्मो की सीमाएं व कानून तय किए गए। इस शोध पत्र में जातिवादी स्थिति व उसको दूर करने के विभिन्न सुधारकों द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया जा रहा है।

मूल शब्द: औनिवेशिक, जातिव्यवस्था, पॉलिटिक्स, स्वदेशी, छुआछूत आदि।

प्रस्तावना

भारत में जातिप्रथा सदियों से चली आ रही थी । इस प्रथा को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने सामाजिक न्याय रूपी तलवार का प्रयोग भारतीय समाज के निम्न वर्ग तथा अछूत के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार एवं तिरस्कार के विरुद्ध किया। उन्हे आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार जातिप्रथा के अन्य सुधारकों में पेरियार का नाम आता है, ये भी जातिविहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे। जातिव्यवस्था को चुनौती देने वाले सुधारकों मे अन्य नामो को भी शामिल किया जाता है, जैसे ज्योतिबा फूल, सावित्रीबाई फुले, राजाराममोहन राय, महात्मा गांधी आदि, जोकि जातिवादी समाज पर कठोर प्रहार करते थे।

सैद्धांतिक अवधारणा

भारत में सामाजिक भेदभाव जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है।इसे लेकर एक ओर एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, जिसने समाज पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और श्रेष्ठ एवं उच्च जाति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की तो दूसरी ओर शोषित और पीड़ित वर्ग अस्तित्व में आया। 19वी सदी में देश के अनेक भागों में अंग्रेज शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा इस व्यवस्था की कमजोरियों को सामने लाने और एक नई चेतना जगाने के उपाय किए गए।

जाति प्रथा भारतीय समाज का बड़ा रोग था जिसके विरुद्ध सुधारकों ने संघर्ष छेड़ा। जातिप्रथा ने समाज में कई दोषों को जन्म दिया था। इसकी वजह से सारा समाज अनेक इकाइयों में विभक्त हो गया था। विभिन्न जातियों, विशेषकर ऊंची और नीची जातियों में काफी वैमनस्य था और सामाजिक एकता छिन्न-भिन्न हो गई थी। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के प्राय: सभी साधन और सुअवसर ऊंची जातियों के हाथ में थे, अत: कालांतर में नीची जातियों का बहुसंख्यक भाग दरिद्र, अशिक्षित और हर दृष्टि से पिछड़ा रह गया। इसका

अर्थ था पूरे राष्ट्र वका पिछड़ापन और सम्पूर्ण राष्ट्र की कमजोरी।

जातिप्रथा और छुआछूत कि नींव प्राचीनकाल में ही पर चुकी थी और तभी से इन्हे दूर करने के असफल प्रयत्न भी होते रहे थे। जातिप्रथा और अस्पृश्यता को दूर करने की दिशा में प्राचीनकाल मे महात्मा बुद्ध ओर महावीर, उसके उपरांत स्वामी रामानंद, कबीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ और नामदेव आदि ने प्रयास किया था पर उन्हे यथोचित सफलता नहीं मिली।

अंग्रेजो के भारत में आगमन के साथ साथ आधुनिक उद्योग, शहरीकरण और परिवहन के नए साधन ने जाति प्रथा और अन्य सामाजिक भेदभावों पर घातक प्रहार किया। इन तत्वों ने सामूहिक एवं व्यक्तिगत संपर्क को अवश्यंभावी कर दिया।विभिन्न उद्योगों में आर्थिक लाभ के सुअवसर ने विशेषकर ऊंची जातियों को किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए बाध्य किया। अब वाणिज्य ओर व्यापार वेश्यो का ही धंधा नहीं रह गया था। पैसे के लिए अब ब्राह्मण भी चमड़े या जुतो का व्यापार कर सकता था।

जातिप्रथा का विरोध और अछूतोत्तर आंदोलन

आधुनिक लोकतांत्रिक विचार, बुद्धिवाद तथा मानववाद से प्रभावित भारतीयों ने धार्मिक अंधविश्वास के साथ ही सामाजिक असमानता, जतिप्रथा और छुआछूत के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यही वजह है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिय जातीय भेदभाव की समाप्ति और व्यापक सामाजिक समता अनिवार्य शर्त बन गए। इस प्रकार शुरू से ही राष्ट्रीय आंदोलन और उसके अभिन्न अंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी जातिगत विशेषाधिकारों और छुआछूत का विरोध किया तथा सभी भारतीयों के लिय समान नागरिक अधिकार, जाति- धर्म- लिंग के भेदभाव के बिना सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिय समान अधिकार एवं स्वतंत्रता की मांग की।

इस दिशा मै विशेषकर छुआछूत समाप्त करने और दलित एवं अछूत वर्ग के उद्धार के लिय गांधी ने भी भरसक प्रयास किए। उन्होंने अछूत वर्ग (शूद्र आदि) को "हरिजन" कहा। उन्होंने उनकी भलाई के लिए हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और "हरिजन सेवक संघ" की स्थापना की।

समाजिक जागृति और शिक्षा के प्रसार से नीची जातियों मे भी जागृति आयी। उन्हे मौलिक मानव अधिकारी का ज्ञान हुआ और वे स्वयं अपने अधिकारी की रक्षा के लिए आगे आने लगे। इस प्रकार उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के सदियों से चले आ रहे शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन ज़ोर पकड़ने लगा।ऐसे आंदोलन के नेताओ मे डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर का नाम उल्लेखनीय है। उनका जन्म एक निम्न परिवार मै गाथा और उन्होंने जातिप्रथा के दोषों को ठीक से समझा था।अत: वे आजीवन जातिप्रथा के खिलाफ, विशेषकर ऊंची जाति की नीची जातियों पर मनमानी के विरुद्ध लड़ते रहे।अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिय उन्होने "ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन" (अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ) की स्थापना की। दलितों एवं अछूत वर्ग के उद्धार के लिय इन जातियों के अन्य नेताओ ने भी "ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन" की स्थापना की। दक्षिण भारत में जातीय कट्टरता और छुआछूत अपनी चरम सीमा पर था। 1920 के बाद वहां गैर-ब्राह्मण जातियों ने एक ' सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट' चलाया और अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की: मंदिर में प्रवेश और ऐसे ही अन्य निषेध के खिलाफ उन्होंने अनेक सत्याग्रह किए।

1947 मे भारत विदेशी शासन से मुक्त हो गया। नए संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को एक दूसरे के साथ समानता का अधिकार दिया गया और छुआछूत, तथा जाति प्रथा को दंडनीय अपराध माना गया। इतना ही नहीं, अछूत, अल्प- संख्यकों और पिछड़ी जातियों की भलाई के लिय विशेष व्यवस्था की गई।

उन्हे नौकरियों में उच्च पद दिए गए और केंद्र तथा राज्यों की सरकारों ने उनके लिए प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया गया।

फिर भी जाति प्रथा अभी भी पुर्णारूप से समाप्त नहीं हो पाई है।आज भी यह देश के सामने एक बड़ी समस्या है। आरक्षण सम्बन्धी विवाद के कारण जातीय भेदभाव हाल के वर्षो में और भी संकीर्ण और कठोर होता जा रहा है

अध्ययन का औचित्य

उपरोक्त अध्यन्न मे हमने औपनिवेशिक काल मे फैली जातिप्रथा व उससे संबंधित विभिन्न आंदोलनों को समझाने कि कोशिश की जोकि हमारे समाज में व्याप्त थे। जातिप्रथा व छुआछूत को मिटाने के लिय कई समजक आंदोलनों, नीतियों और महापुरुषों ने महत्वूर्ण भूमिक निभाई जिसको देखते हुए जातिप्रथा को शोध के रूप में चुना गया। इस शोध मे यह भी प्रदर्शित किया गया है कि 1947 के बाद संविधान मे को चुनौती देने क्या क्या प्रावधान किए गए।

उद्देश्य

1. उन ऐतिहासिक कारकों को पहचानना जिसके तहत जातिप्रथा भारत मै सदियों से प्रचलित रही।
2. 1947 के बाद संविधान मे सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिय किए गए प्रावधानों को प्रदर्शित करना।
3. समाज में दलित उत्थान के लिए किए गए आंदोलनों को प्रदर्शित करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत सोध पत्र एतिहासिक विश्लेषण विधि पर आधारित है। इसके लिए शोध सामग्री को प्रशिद्ध पुस्तकों से किया गया है। चूंकि शोध कार्य द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है इसलिए शोधकर्ता द्वारा अनुभाविक दृष्टिकोण अपनाकर शोध कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावित शोध का योगदान

यह शोध समाज मै फैली कुरीति को समझने मे एक छोटा सा योगदान मात्र होगा। शिक्षा जगत में इस योगदान को निम्न प्रकार से आंका जा सकेगा –

1. औपनिवेशिक काल का प्रभाव आज की जातिव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष तौर पर किया ना रहा है। यह विभिन्न शोध से भी स्पष्ट हुआ है। प्रस्तुत शोध उस प्रभाव को एतिहासिक व समसामयिक दृष्टि से समझने की दृष्टि प्रदान करने में सहायक होगा।
2. इतिहास की पृष्ठभूमि वाले शोधार्थियों को को जातिव्यवस्था को समझने के लिय अध्यनन मे रुचि रखते है, उनके की विभिन्न शोधों के द्वार खोलने में सहायता देगा।

संदर्भ

1. वरमानीी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन, नई दिल्ली, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, 1979
2. शुक्ल., आधुनिक भारत का इतिहास, नई दिल्ली, ख्वाजा प्रेस,2006
3. अंग्रेजो ने भारत में जाति व्यवस्था का बीज कैसे बिया (लेख), संजोए चक्रवती (प्रोफेसर, टैंपल यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया, अमेरिका), 2019
4. Gaba OP. Principles of political theory, Noida, Mayur paperbex, 2005.
5. Vermani RC. British colonialism in India, New Delhi, Authors Guild, 1983.
6. Brass Paul R. Language, Religion and Politics in North India, 1979.
7. Frykenburg RE. (ed.), Land control and social structure in Indian History, London, 1969.